



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 107]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 11, 2016/चैत्र 22, 1938

No. 107]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 11, 2016/ CHAITRA 22, 1938

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2016

**विषय :** चीन जन. गण., जापान, रूस, कोरिया गणराज्य, ब्राजील और इंडोनेशिया के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "इस्पात के अलॉय या गैर-अलॉय हाट-रोल्ड फ्लैट उत्पादों 2100 मिमी. तक की चौड़ाई और 25 मिमी. तक मोटाई की काइलों में और इस्पात के अलॉय या गैर-अलॉय हाट-रोल्ड फ्लैट उत्पादों जो 4950 मिमी. तक की चौड़ाई और 150 मिमी. तक मोटाई के जो काइलों में न हो (जिसे शीटों और प्लेटों के रूप में जाना जाता है)" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

**सं. 14/9/2016 –डीजीएडी.—** मै. स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि, में. जेएसडब्ल्यू स्टील लि. और में. एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड (जिन्हें आगे याचिकाकर्ता कंपनियां या आवेदक भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष एक याचिका दायर की है जिसमें चीन जन. गण., जापान, रूस, कोरिया गणराज्य, ब्राजील और इंडोनेशिया (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "इस्पात के अलॉय या गैर-अलॉय हाट-रोल्ड फ्लैट उत्पादों 2100 मिमी. तक की चौड़ाई और 25 मिमी. तक मोटाई की काइलों में और इस्पात के अलॉय या गैर-अलॉय हाट-रोल्ड फ्लैट उत्पादों जो 4950 मिमी. तक की चौड़ाई और 150 मिमी. तक मोटाई के जो काइलों में न हो (जिसे शीटों और प्लेटों के रूप में जाना जाता है)" (जिसे आगे संबद्ध वस्तु या विचाराधीन उत्पाद भी कहा गया है) के कथित पाटित आयातों पर पाटनरोधी जांच की शुरूआत और उन पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है।

- और यतः प्राधिकारी प्रथम दृष्टया यह पाते हैं कि संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं जो पाटनरोधी जांच की शुरूआत का उचित ठहराते हैं,

इसलिए प्राधिकारी एतद्वारा उक्त नियमावली के अनुसार कथित पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति की जांच की शुरूआत करते हैं ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई 'क्षति' को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

### **विचाराधीन उत्पाद**

3. वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद "इस्पात के अलॉय या गैर-अलॉय हाट-रोल्ड फ्लैट उत्पादों 2100 मिमी. तक की चौड़ाई और 25 मिमी. तक मोटाई की काइलों में और इस्पात के अलॉय या गैर-अलॉय हाट-रोल्ड फ्लैट उत्पादों जो 4950 मिमी. तक की चौड़ाई और 150 मिमी. तक मोटाई के जो काइलों में न हो (जिसे शीटों और प्लेटों के रूप में जाना जाता है)" है। पीयूसी में ऐसे उत्पाद शामिल हैं, जो हाट रोल्ड से आगे निर्मित नहीं हों, और लोहे, अलाय या गैर-अलाय इस्पात के प्राइम या गैर प्राइम दशा में हों, जिसका यथा-रोल्ड किनारा या ट्रिम्ड किनारा या स्लिट किनारा या मिल्ड किनारा या शीयर्ड किनारा या लेजर कट किनारा या गैस कट किनारा या किसी अन्य प्रकार का किनारा हो। ये उत्पाद पिकल्ड या गैर-पिकल्ड (स्किन-पास या टेम्परिंग सहित या उसके बिना), स्लिट या गैर-स्लिट, सामान्यीकृत या असामान्यीकृत, पराध्वनि परीक्षित या अपरीक्षित या आयल्ड या गैर-आयल्ड हो सकते हैं। ये उत्पाद "यथा-रोल्ड" या "थर्मो-मैकेनिकली रोल्ड" या "थर्मो-मैकेनिकली नियंत्रित रोल्ड" या नियंत्रित रोल्ड या "सामान्यीकृत रोल्ड" या "सामान्यीकृत" या इसी प्रकार की किसी अन्य प्रक्रिया के अधीन हो सकते हैं। इन उत्पादों में हाट रोलिंग के दौरान सीधे उत्पन्न विभिन्न प्रकारों के रिलीफ/चेकर्ड प्रवृत्ति हो सकती है। इन उत्पादों को पिकलिंग, आयलिंग, रीवाइंडिंग, रीकाइलिंग, टेपर रोलिंग ताप उपचार आदि जैसे विभिन्न प्रसंस्करण चरणों के अधीन रखा जा सकता है। इन उत्पादों को सेंड ब्लास्टेड या शाट ब्लास्टेड या समान प्रक्रिया के अधीन रखा जा सकता है। पीयूसी में हाट रोल्ड फ्लैट शीटें और अलाय या गैर-अलाय इस्पात की प्लेटें शामिल हैं चाहे रीवर्सिबल प्लेट मिल या हाट स्ट्रिप मिल या टेंडेम मिल या स्टेकेल मिल या किसी अन्य प्रक्रिया सहित 2-हाई, 3-हाई, 4-हाई, क्लस्टर मिल या किसी समान हाट रोलिंग प्रक्रिया सहित विभिन्न प्रकार की रोलिंग व्यवस्था के साथ यूनिवर्सल प्लेट मिल से रोल्ड हो अथवा नहीं, पीयूसी में हाट रोलिंग प्रक्रिया से सीधे या हाट रोल्ड काइलों से कट/शीयर्ड से उत्पादित शीटें और प्लेटें शामिल हैं। निम्नलिखित को विचाराधीन उत्पाद के दायरों में शामिल नहीं किया जाता है:

(क) स्टेनलैस स्टील के हाट रोल्ड फ्लैट उत्पाद

(ख) स्टील के हाट रोल्ड फ्लैट उत्पाद जो इलेक्ट्रो लिटिकली प्लेटेड या जिंक से कोटेड हों।

(ग) स्टील के हाट रोल्ड फ्लैट उत्पाद जो अन्यथा जिंक से प्लेटेड या कोटेड हों।

(घ) क्लेडेड स्टील

4. पीयूसी को अनेक अनुप्रयोगों और क्षेत्रों जैसे आटोमोटिव, तेल और गैस लाइन पाइप/उत्खनन, कोल्ड-रोलिंग, पाइप और ट्यूब विनिर्माण, अवसंरचना और निर्माण, सामान्य इंजीनियरिंग और फेब्रिकेशन, जमीन खोदने और खनन उपकरण, भण्डारण टैंकों, लो प्रेशर हीटर्स, सीमेंट, उर्वरक, रीफाइनरी आदि के लिए संयंत्र और प्रक्रिया उपकरण सहित पूंजीगत सामान में प्रयोग किया जाता है।

5. पीयूसी को सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष 7208, 7211, 7225 और 7226 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक हैं और वर्तमान जाँच के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं हैं।

### **समान वस्तु**

6. आवेदक ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित की जा रही संबद्ध वस्तु और भारत में पाटित की जा रही संबद्ध वस्तु समान वस्तुएं हैं। आवेदकों ने दावा किया है कि आवेदकों द्वारा उत्पादित की जा रही और संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से आयात किया जा रहा विचाराधीन उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए नियमों के अंतर्गत इन्हें समान वस्तु माना जाना चाहिए। अतः वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ भारत में आवेदकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से आयातित की जा रही संबद्ध वस्तु के 'समान वस्तु' माना जा रहा है।

**घरेलू उद्योग**

7. यह आवेदन मै. स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि, मै. जेएसडब्ल्यू स्टील लि. और मै. एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। रिकार्ड में उपलब्ध सूचना के अनुसार पूर्वोक्त तीन उत्पादकों के उत्पादन का भारतीय उत्पादन में कुल घरेलू उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बनता है। इसके अलावा यह आवेदन दो घरेलू उत्पादकों अर्थात् टाटा स्टील लिमिटेड और जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड द्वारा समर्थित है।

8. इस प्रकार, आवेदन पूर्वोक्त तीन घरेलू उत्पादकों की योग्यता के संबंध में नियमावली के नियम 2(ख) और नियम 5(3) की अपेक्षाओं को पूरा करता है और यह कि उन्हें संबंधित नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग (डीआई) माना जाता है।

**शामिल देश**

9. वर्तमान जांच में शामिल देश चीन जन. गण., जापान, रूस, कोरिया गणराज्य, ब्राजील और इंडोनेशिया हैं।

**सामान्य मूल्य****जापान, कोरिया गणराज्य, रूस, ब्राजील और इंडोनेशिया**

10. आवेदकों ने जापान, कोरिया गणराज्य, रूस और ब्राजील के लिए सामान्य मूल्य को इन देशों के अपने-अपने मेटल बुलेटिन रीसर्च वीकली ट्रेकर फार स्टील में बताई गई घरेलू कारखाना-द्वार कीमत के आधार पर निर्धारित की है। इंडोनेशिया के संबंध में आवेदकों ने इंडोनेशियाई उत्पादक द्वारा उसके घरेलू उपभोक्ताओं के लिए जारी किए घरेलू बिक्री बीजकों पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए भरोसा किया गया है।

**चीन जन. गण.**

11. चीन जन. गण. के संबंध में, आवेदकों ने बताया है कि चीन जन. गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाना चाहिए और सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 और 8 के अनुसार किया जाना चाहिए। नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 8 के अनुसार, यह माना गया है कि चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तु के उत्पादक गैर बाजार अर्थव्यवस्था के अधीन प्रचालनरत हैं। उक्त गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की मान्यता और प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा उसके खंडन के अधीन चीन जन. गण. के लिए संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य का अनुमान नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 के अनुसार किया गया है। आवेदकों ने प्रतिनिधि देश के रूप में जापान का सुझाव दिया है और चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण जापान में प्रचलित कीमत के आधार पर किया है। प्राधिकारी एतद्वारा चीन जन. गण. के लिए प्रतिनिधि देश के रूप में जापान की उपयुक्तता के बारे में अनुबंध 1 के पैरा 7 के अनुसार सभी हितबद्ध पक्षों से टिप्पणियां आमंत्रित करते हैं।

**निर्यात कीमत**

12. आवेदक ने भारत में आईबीआईएस से उपलब्ध सौदावार आयात आकड़ों के आधार पर सभी संबद्ध देशों के लिए निर्यात कीमत निर्धारित की है। अंतर्देशीय भाड़े, समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, सीमाशुल्क प्रहस्तन और निकासी प्रभारों और वैट के गैर-वापसी योग्य हिस्से (केवल चीन जन. गण. के लिए) के संबंध में कीमत समायोजन किए गए हैं।

**पाटन मार्जिन**

13. सामान्य मूल्य की तुलना कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत के साथ की गई है जो संबद्ध देशों के संबंध में पर्याप्त पाटन मार्जिन दर्शाती है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य कारखाना-द्वार निर्यात कीमत से काफी अधिक है जिससे प्रथम दृष्टया पता चलता है कि संबद्ध देशों से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है।

14. भारी पाटन मार्जिन के पर्याप्त प्रथम-दृष्टया साक्ष्य हैं जो पाटनरोधी जाँच की शुरूआत को उचित ठहराते हैं।

**क्षति और कारणात्मक संबंध**

15. आवेदकों ने दावा किया है कि संबद्ध देशों से कथित पाटन के परिणामस्वरूप उन्हें वास्तविक क्षति हुई है और उन्होंने क्षति के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं जो आयातों में समग्र रूप से और घरेलू उत्पादन और घरेलू मांग के संबंध में वृद्धि के रूप में हुई

है। संबद्ध देशों से पाटन के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की बिक्री, उत्पादन, क्षमता उपयोग, बाजार हिस्से, मालसूची, लाभ, नियोजित पूंजी पर आय, नकद लाभ आदि में गिरावट आई है।

16. आवेदकों ने प्रतिकूल कीमत प्रभावों का भी दावा किया है जो कीमत ह्रास, कम कीमत पर बिक्री और कीमत कटौती/कीमत न्यूनीकरण से साक्ष्यांकित होता है। प्राधिकारी मानते हैं कि संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण आवेदकों को क्षति होने के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद हैं जो पाटनरोधी जाँच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराते हैं।

### **जांच अवधि**

17. वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ जांच अवधि (पीओआई) जुलाई, 2015 से दिसम्बर, 2015 तक की है। तथापि, क्षति जाँच अवधि में अप्रैल 2012 से मार्च 2013, अप्रैल 2013 से मार्च 2014, अप्रैल 2014 से मार्च 2015, अप्रैल 2015 से दिसंबर 2015 (वार्षिकीकृत) और जांच की अवधि (पीओआई) शामिल होगी।

### **पूर्व प्रभाव से शुल्क लगाना**

18. आवेदकों ने निम्नलिखित कारणों की वजह से पूर्व प्रभाव से पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए अनुरोध किया है:

क. पाटन का इतिहास है और आयातकों को इस बात से अवगत होना चाहिए कि क्षति होती है।

ख. घरेलू उद्योग को क्षति तुलनात्मक कम समय में संबद्ध वस्तुओं के बड़े पैमाने पर पाटन के कारण हुई है जिनके समय पाटित आयातित संबद्ध वस्तुओं की मात्रा तथा अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लगाए जाने वाले पाटनरोधी शुल्क के उपचारात्मक प्रभाव का गंभीरतापूर्वक क्षीण होने की संभावना है।

19. हितबद्ध पक्षकार इस संबंध में अपने अनुरोध कर सकते हैं।

### **सूचना प्रस्तुत करना**

20. संबद्ध देश में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकार, संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले भारत में ज्ञात आयातकों व प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को अलग-अलग सूचित किया जा रहा है ताकि वे नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत कर सकें। कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से जाँच से संगत अनुरोध कर सकता है। सूचना/अनुरोध निम्नलिखित को प्रस्तुत किए जाए:

#### **निर्दिष्ट प्राधिकारी**

**पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय**

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय**

**वाणिज्य विभाग**

**भारत सरकार**

**चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5 संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001**

### **समय-सीमा**

21. वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई सूचना इस जाँच की शुरुआत के पत्र की तारीख से चालीस दिनों (दिनों 40) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

22. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस समीक्षा जांच की शुरुआत की अधिसूचना की तारीख से दिनों के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित 40 (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें। यह सूचना मूल प्रति तथा साफ्ट प्रति दोनों में ही प्रस्तुत की जानी चाहिए।

**गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना**

23. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए उसके किसी भाग के संबंध में "गोपनीयता" का दावा करने के मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा:-

(क) गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि); और

(ख) अगोपनीय रूप में अंकित दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि)।

24. "गोपनीय" या "अगोपनीय" अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। दोनों पाठों की हार्ड कॉपियों के साथ साफ्ट कॉपियां पाँच (5) सैट में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

25. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

26. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

27. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

28. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

29. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

**सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण**

30. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

**असहयोग**

31. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

ए. के. भल्ला, अतिरिक्त सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)****INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th April, 2016

**Subject: - Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of “Hot-rolled flat products of alloy or non-alloy steel in coils of a width upto 2100mm and thickness upto 25mm and Hot-rolled flat products of alloy or non-alloy steel not in coils (commonly known as sheets and plates) of a width upto 4950mm and thickness upto 150mm”, originating in or exported from China PR, Japan, Russia, Korea RP, Brazil and Indonesia.**

**No. 14/9/2016-DGAD.**—M/s Steel Authority of India Limited, M/s. JSW Steel Limited and M/s Essar Steel India Limited (hereinafter also referred to as petitioner companies or the applicants) have filed a petition before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) for initiation of anti-dumping investigation and imposition of anti-dumping duty on the alleged dumped imports of “Hot-rolled flat products of alloy or non-alloy steel in coils of a width upto 2100mm and thickness upto 25mm and Hot-rolled flat products of alloy or non-alloy steel not in coils (commonly known as sheets and plates) of a width upto 4950mm and thickness upto 150mm” (hereinafter also referred to as the subject goods or the Product Under Consideration), originating in or exported from China PR, Japan, Russia, Korea RP, Brazil and Indonesia (hereinafter also referred to as the subject countries).

2. And whereas, the Authority prima facie finds that sufficient evidence of dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject countries, injury to the domestic industry and causal link between the alleged dumping and the injury exist to justify initiation of an anti-dumping investigation, the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping causing consequent injury to the domestic industry in terms of the Rules, to determine the existence, degree and effect of dumping and recommend the amount of anti dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

**Product under Consideration**

3. The product under consideration (PUC) in the present investigation is “Hot-rolled flat products of alloy or non-alloy steel in coils of a width upto 2100mm and thickness upto 25mm and Hot-rolled flat products of alloy or non-alloy steel not in coils (commonly known as sheets and plates) of a width upto 4950mm and thickness upto 150mm”. The PUC covers products which are not further worked than hot-rolled and are flat products of iron, alloy or non-alloy steel, in prime or non-prime condition having ‘as-rolled’ edge or ‘trimmed’ edge or ‘slit’ edge or ‘milled’ edge or “sheared” edge or “laser-cut” edge or “gas-cut” edge or any other type of edges. These products may be pickled or non-pickled (with or without skin-pass or tempering), slit or non-slit, normalized or un-normalized, ultra-sonically tested or untested or oiled or non-oiled etc. These products may be “as-rolled” or “thermo-mechanically rolled” or “thermo-mechanically controlled rolled” or “controlled rolled” or “normalized rolled” or “normalized” or subject to any other similar process. These products may have patterns in relief / chequered patterns of different types derived directly during hot rolling. These products may have been subjected to various processing steps like pickling, oiling, rewinding, recoiling, temper rolling, heat treatment, etc. These products may be sand blasted or shot blasted or subjected to similar processes. The PUC covers hot rolled flat sheets and plates of alloy or non-alloy steel, whether or not rolled from universal plate mill including reversible plate mill or hot strip mill or tandem mill or steckel mill or any other similar process with various type of rolling configuration including 2-High, 3-High, 4-High, cluster mill or any similar hot rolling process. The PUC includes sheets and plates produced either directly from the hot rolling process or cut / sheared from hot rolled coils. The following are not included in the scope of the product under consideration:

- a) Hot-rolled flat products of stainless steel.
- b) Hot-rolled flat products of steel which are electrolytically plated or coated with zinc.
- c) Hot-rolled flat products of steel otherwise plated or coated with zinc.
- d) Cladded steel.

4. The PUC is used in many applications and sectors such as automotive, oil and gas line pipes/exploration, cold-rolling, pipe and tube manufacturing, infrastructure and construction, general engineering & fabrication, earth-moving & mining equipment, storage tanks, low pressure heaters, capital goods including plant and process equipment for cement, fertilizer, refineries etc.

5. The PUC is classified under Custom Tariff Heading 7208, 7211, 7225 and 7226. The Customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

**Like Article**

6. The applicants have claimed that the subject goods being produced by the domestic industry are similar to the subject goods being dumped into India. The applicants have claimed that PUC produced by the applicants and originating in or imported from the subject countries are having comparable characteristics in terms of parameters such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable and hence should be treated as 'like article' under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the applicants in India are being treated as 'like article' to the subject goods originating in or imported from the subject countries.

**Domestic Industry**

7. The application has been filed by M/s Steel Authority of India Limited, M/s. JSW Steel Limited and M/s Essar Steel India Limited. As per the information available on record, the production of the aforesaid three producers accounts for a major proportion of the total domestic production in India. The Application has also been supported by two other domestic producers, namely, Tata Steel Limited and Jindal Steel and Power Limited.

8. The application, thus, satisfies the requirements of Rule 2(b) and Rule 5(3) of the Rules with regard to standing of the aforesaid three domestic producers and that they are treated as domestic industry (DI) within the meaning of Rule 2(b) supra.

**Countries involved**

9. The countries involved in the present investigation are China PR, Japan, Russia, Korea RP, Brazil and Indonesia.

**Normal Value****Japan, Korea RP, Russia, Brazil and Indonesia**

10. The applicants have determined the normal value for Japan, Korea RP, Russia and Brazil on the basis of the domestic ex-works price as reported in Metal Bulletin Research Weekly Tracker for Steel for these respective countries. In respect of Indonesia, the applicants have relied upon the domestic sales invoices issued by an Indonesian producer to its domestic customers to determine the normal value.

**China PR**

11. With regard to China PR, the applicants have submitted that China PR should be treated as a non-market economy country and have determined the normal value in accordance with Para 7 and 8 of Annexure I of the Rules. In terms of Para 8 of Annexure 1 to the Rules, it is presumed that the producers of the subject goods in China PR are operating under non-market economy conditions. In view of the non-market economy presumption and subject to rebuttal of the same by the responding exporters, the normal value of the subject goods in China PR has been estimated in terms of Para 7 of Annexure 1 to the Rules. The applicants have suggested Japan as surrogate country and determined normal value in China PR as per the prices prevailing in Japan. The Authority hereby invites comments from all interested parties in accordance with para 7 of Annexure I about appropriateness of Japan as a surrogate country for China PR.

**Export Price**

12. The applicants have determined the export price for the product under consideration for all the subject countries based on the transaction wise import data available from IBIS in India. Price adjustments have been made on account of inland freight, ocean freight, ocean insurance, custom handling & clearance charges and non-refundable portion of VAT (only for China PR).

**Dumping Margin**

13. The normal values and the export prices have been compared at ex-factory level, which show significant dumping margins in respect of the subject countries. There is sufficient prima facie evidence that the normal values of the subject goods in the subject countries are significantly higher than the ex-factory export prices, indicating, prima facie, that the subject goods are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject countries.

14. There is sufficient prima-facie evidence of the significant dumping margins to justify initiation of antidumping investigation.

**Injury and Causal Link**

15. The applicants have claimed that they have suffered material injury and have furnished evidence regarding the injury having taken place as a result of the alleged dumping from the subject countries in terms of increase in imports in absolute terms and in relation to domestic production and domestic demand. The dumping from the subject countries has

resulted in deterioration of sales, production, capacity utilisation, market share, inventories, profits, return on capital employed, cash profit etc. of the domestic industry.

16. The applicants have also claimed adverse price effects as evidenced by price suppression, price depression and price undercutting/underselling. The Authority considers that there is sufficient prima facie evidence of injury being suffered by the applicants caused by the dumped imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries to justify initiation of an antidumping investigation.

#### **Period of Investigation**

17. The period of investigation (POI) for the present investigation is from July, 2015 to December, 2015. The injury investigation period will, however, cover the periods April 2012-March 2013, April 2013-March 2014, April 2014-March 2015, April 2015-Dec 2015 (Annualized) and the POI.

#### **Retrospective imposition of duties**

18. The applicants have requested for retrospective imposition of the antidumping duty due to following reasons:

- a. There is history of dumping and that the importers should have been aware that exporters practice dumping and that such dumping caused injury to the domestic industry
- b. The injury to the domestic industry has been caused by massive dumping of the subject goods in a relatively short time which in the light of the timing and volume of imported subject goods dumped and other circumstances is likely to seriously undermine the remedial effect of the antidumping duty liable to be levied.

19. The interested parties may make their submissions in this regard.

#### **Submission of information**

20. The known exporters in the subject countries and their Governments through their Embassies in India, importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time limit set out below. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time limit set out below. The information/submissions may be submitted to:

The Designated Authority,  
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties,  
Ministry of Commerce & Industry,  
Department of Commerce  
Government of India  
4th Floor, Jeevan Tara Building, 5, Parliament Street,  
New Delhi-110001

#### **Time Limit**

21. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 days) from the date of issuance of the letter intimating initiation of the investigation. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the AD Rules.

22. All interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application within forty days (40 days) from the date of issuance of the letter intimating initiation of the investigation. The information must be submitted in hard copies as well as in soft copies.

#### **Submission of information on confidential basis**

23. The parties making any submission (including Appendices/Annexure attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file the same in two separate sets, in case "confidentiality" is claimed on any part thereof:-

- a) one set marked as Confidential (with title, number of pages, index, etc.), and
- b) the other set marked as Non-Confidential (with title, number of pages, index, etc.).



24. The “confidential” or “non-confidential” submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions. Soft copies of both the versions will also be required to be submitted, along with the hard copies, in five (05) sets of each.

25. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

26. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, a party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

27. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

28. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

29. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

#### **Inspection of Public File**

30. In terms of Rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

#### **Non-cooperation**

31. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

A. K. BHALLA, Additional Secretary & Designated Authority